रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 641] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 22, 2006/आषाढ़ 1, 1928
No. 641] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 22, 2006/ASADHA 1, 1928

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2006

का.आ. 928(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

श्री मुकुल राय, महासचिव, आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, 30बी, हरीश चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन श्री नीलोत्पल बासु, जो तत्समय राज्य सभा के आसीन सदस्य थे, श्री सोमनाथ चटर्जी, संसद सदस्य (लोक सभा), श्री मो. सलीम, संसद सदस्य (लोक सभा), श्री हन्नान मोल्लाह, संसद सदस्य (लोक सभा), श्री लक्ष्मण सेठ, संसद सदस्य (लोक सभा), श्री अमितव नन्दी, संसद सदस्य (लोक सभा), श्री सुधांशु सिल, संसद सदस्य (लोक सभा), श्री तारित बरान तोपदार, संसद सदस्य (लोक सभा), श्री बंसागोपाल चौधरी, संसद सदस्य (लोक सभा) और श्री (डा.) सूजान चक्रवर्ती, संसद सदस्य (लोक सभा) की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 8 मार्च, 2006 की याचिका प्रस्तुत की गई है;

और उक्त याची ने अपनी याचिका में यह अभिकथन किया है कि श्री नीलोत्पल बासु पश्चिमी बंगाल राज्य ग्रामीण संचय सोसाईटी (ग्रासों) में लाभ का पद धारण कर रहे थे;

और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन एक निर्देश, तारीख 20 मार्च, 2006 द्वारा इस बारे में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई थी कि क्या श्री नीलोत्पल बासु और नौ अन्य संसद सदस्य संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उप-खंड (क) के अधीन संसद सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गये हैं;

और निर्वाचन आयोग को 20 मार्च, 2006 को निर्देश प्राप्त हुआ था और कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, 2 अप्रैल, 2006 को श्री नीलोत्पल बासु की राज्य सभा की सदस्यता का कार्यकाल समाप्त हो गया था;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि इस तथ्य के कारण कि श्री नीलोत्पल बासु की राज्य सभा में सदस्यता का कार्यकाल पहले ही 2 अप्रैल, 2006 को समाप्त हो चुका है और इस प्रकार वे अब संसद सदस्य नहीं हैं, उक्त निर्देश, जहां तक वह श्री नीलोत्पल बासु के राज्य सभा का सदस्य बने रहने के लिए उनकी अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित है, निरर्थक हो गया है;

और निर्वाचन आयोग नौ अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के मामलों पर पृथक रूप से कार्यवाही करने का प्रस्ताव करता है क्योंकि वे मामले भिन्न हैं;

अतः, अब, मैं, आ. प. जै. अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूं कि श्री मुकुल राय की उक्त याचिका, जहां तक वह श्री नीलोत्पल बासु के राज्य सभा का सदस्य बने रहने के लिए उनकी अभिकथित निरर्हता से संबंधित है, 2 अप्रैल, 2006 को श्री नीलोत्पल बासु की राज्य सभा की सदस्यता का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण निरर्थक हो गई है ।

भारत का राष्ट्रपति

20 जून, 2006

[फा. सं. एच-11026(13)/2006-लेग. II]

एन. के. नम्पूथिरी, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी

उपाबन्ध

भारत निर्वाचन आयोग

निर्देश :

संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन पूर्व राज्य सभा सदस्य श्री नीलोत्पल बासु की अभिकथित निरर्हता

2006 का निर्देश मामला सं. 3

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

राय

यह संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त तारीख 20 मार्च, 2006 का निर्देश है जिसके द्वारा इस प्रश्न पर भारत के निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री नीलोत्पल बासु, जो तत्समय राज्य सभा के आसीन सदस्य थे, श्री सोमनाथ चटर्जी, संसद सदस्य (लोक सभा), श्री मो सलीम, संसद सदस्य (लोक सभा), श्री हन्नान मोल्लाह, संसद सदस्य (लोक सभा), श्री लक्ष्मण सेठ, संसद सदस्य (लोक सभा), श्री अमितव नन्दी, संसद सदस्य (लोक सभा), श्री सुधांशु सिल, संसद सदस्य (लोक सभा), श्री तारित बरान तोपदार, संसद सदस्य (लोक सभा), श्री बंसागोपाल चौधरी, संसद सदस्य (लोक सभा) और श्री (डा.) सूजान चक्रवर्ती, संसद सदस्य (लोक सभा) संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संबंधित सदन के सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं अथवा नहीं ।

2. उपर्युक्त दस संसद सदस्यों की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न श्री मुकुल राय, महासचिव, आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, 30 बी, हरीश चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत तारीख 8 मार्च, 2006 की एकल याचिका में उठाया गया था ।

3. यह राय श्री नीलोत्पल बासु की राज्य सभा का सदस्य होने के लिए अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित है । याची ने यह अभिकथन किया है कि श्री नीलोत्पल बासु, पश्चिमी बंगाल राज्य ग्रामीण संचय सोसाइटी (ग्रासो) में पद धारण कर रहे थे । याची के अनुसार उक्त पद लाभ का पद था और इस प्रकार श्री बासु राज्य सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हित हुए थे । याची ने यह दलील दी थी कि इसे ध्यान में रखते हुए श्री बासु को संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन राज्य सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हित किया जाना चाहिए ।

4. आयोग में राष्ट्रपति से निर्देश तारीख 20 मार्च, 2006 को प्राप्त हुआ था । श्री मुकुल राय की याचिका के साथ ऐसा कोई दस्तावेज नहीं लगा था, जो किसी भी संसद सदस्य की ऐसे संबंधित पदों, जिन्हें अभिकथित रूप से लाभ के पद कहा गया था, पर अभिकथित नियुक्ति की उनकी दलील का समर्थन करता हो । इसके अतिरिक्त, श्री मुकुल राय की याचिका में श्री बासु सहित संसद सदस्यों की याची द्वारा निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति की तारीख के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट कथन भी अंतर्विष्ट नहीं था । अतः याची को आयोग की तारीख 24 मार्च, 2006 की सूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था । याची ने तारीख 15 अप्रैल, 2006 का एक पत्र प्रस्तुत किया जिसके साथ कतिपय दस्तावेज लगे थे किन्तु उनमें पुनः मांगी गई विनिर्दिष्ट जानकारी अंतर्विष्ट नहीं थी । अतः, याची को पुनः तारीख 3 मई, 2006 की सूचना द्वारा 24 मई, 2006 तक विनिर्दिष्ट जानकारी, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था । उक्त सूचना के उत्तर में याची ने 24 मई, 2006 को एक पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें अन्य बातों के साथ यह दलील दी गई थी कि उसके द्वारा प्रथम दृष्ट्या जानकारी पहले ही उपलब्ध करा दी गई थी ।

5. राष्ट्रपति से निर्देश प्राप्त होने के समय और साथ ही उस समय भी जब याची को याचिका में लिखित दस संसद सदस्यों की अभिकथित नियुक्ति के संबंध में विनिर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए सूचना जारी की गई थी, श्री बासु राज्य सभा के आसीन सदस्य थे । उसी दौरान, 2 अप्रैल, 2006 को श्री निलोत्पल बासु का राज्य सभा के सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया और वे उस तारीख से उस सदन के सदस्य नहीं रहे ।

6. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि श्री नीलोत्पल बासु का राज्य सभा के सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इसलिए उनका मामला तारीख 8 मार्च, 2006 की याचिका में निर्दिष्ट अन्य नौ संसद सदस्यों के मामलों की तुलना में भिन्न हो गया है और इसलिए श्री बासु के मामले को अन्य संसद सदस्यों के मामलों से अलग कर दिया गया है, और यह राय श्री बासु की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर प्रस्तुत की जा रही है ।

7. तारीख 2.4.2006 को राज्य सभा की सदस्यता से श्री बासु की सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा विचार किए जाने हेतु उदभूत प्रारंभिक विवाद्यक यह है कि क्या निर्दिष्ट याचिका में उठाया गया उनकी अभिकथित निरर्हता का प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन आयोग की किसी राय के लिए अब भी जीवित है अथवा नहीं और क्या उसे प्रारंभ से विनिश्चय किए जाने की आवश्यकता है ।

8. संविधान के अनुच्छेद 103(2) और अनुच्छेद 192(2) के अधीन राष्ट्रपति और राज्यपालों से निर्देशों के मामलों में आयोग के समक्ष कार्यवाहियां न्यायिककल्प कार्यवाहियां होती हैं । अतः, ऐसे मामलों में आयोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अंगीकार किए गए सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और नीति द्वारा मार्गदर्शित होता है और उनका अनुसरण करता है । एक साधारण सिद्धांत के रूप में न्यायालय पक्षकारों के बीच जीवित विवाद्यकों पर विचार करते हैं और ऐसे विवाद्यक पर विनिश्चय करने के लिए विचार नहीं करते जो विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक मात्र होता है या किसी बाद में घटित होने वाली घटना के कारण निरर्थक हो गया है । ऐसे मामलों

में जिनमें निर्वाचन अपील के लंबित रहने के दौरान, अभ्यर्थी जिसके निर्वाचन को चुनौती दी गई थी, उसकी मृत्यु या संबंधित सदन में स्थान से उसके त्यागपत्र पर या जहां स्वयं सदन ही विघटित कर दिया गया हो, संबंधित सदन का सदस्य नहीं रहता, उच्चतम न्यायालय ने अपील को निरर्थक अपील के रूप में माना है और उस आधार पर अपील को खारिज कर दिया है । पोडीपीरेड्डी अच्यूत देसाई बनाम चिन्नम जोगाराव [(1987) सप्लिमेंटरी एससीसी 42] के मामले में जहां सदन निर्वाचन अपील के लंबित रहने के दौरान विघटित कर दिया गया था, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :

" इस निर्वाचन अपील में उठाए गए प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण हैं । हम अपीलार्थी की ओर से दी गई दलीलों में बल भी देख रहे हैं । इसी तरह, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नए रूप से निर्वाचन पहले ही हो चुके हैं और इस रूप में अपील निरर्थक हो गई है, यदि हम निर्वाचन अर्जी को खारिज करने में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए मत की विधिमान्यता या अन्य प्रारूप में जांच करें तो हम बेकार में ही अपनी शक्ति गवाएंगे । हम, इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय की विनिश्चय की विधिमान्यता पर या अन्य पहलू पर कोई राय चाहे वह किसी तरह की हो, व्यक्त किए बिना यह निदेश देते हैं कि यह अपील खर्चे के बारे में कोई आदेश किए बिना निपटाई गई समझी जाएगी ।"

9. पूर्व में उच्चतम न्यायालय ने लोकनाथ पधान बनाम वीरेन्द्र कुमार साहु (एआईआर 1974 एससी 505) के मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था :

" विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण, प्रत्यर्थी के निर्वाचन को अपास्त करना निरर्थक होगा और उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, अतः न्यायालय को अपील में उदभूत प्रश्न के गुणागुण पर विचार-विमर्श करने से इंकार कर देना चाहिए । हम यह मानते हैं कि प्रत्यर्थी की ओर से दी गई इस प्राथमिक दलील में काफी बल है । भारत तथा इंग्लैड में मान्यताप्राप्त और अनुसरित सुस्थापित यह पद्धति है कि न्यायालय को ऐसे विवाद्यक का विनिश्चय करने के लिए तब तक विचार नहीं करना चाहिए जब तक कि वह विवाद्यक पक्षकारों के बीच में जीवित न हो । यदि कोई विवाद्यक विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक मात्र हो और उसके विनिश्चय से पक्षकारों की स्थिति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो यह लोक समय की बर्बादी ही होगी और न्यायालय के लिए इसका विनिश्चय करने में स्वयं को लगाए रखने में उसके प्राधिकार का उचित प्रयोग भी नहीं है.....

.....प्रस्तुत मामले में, उड़ीसा विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण इस बारे में विचार करना सैद्धान्तिक मात्र हो गया है कि क्या उस तारीख को जब नामांकन फाइल किया गया था, प्रत्यर्थी नियम 9-क के अधीन निरर्हित था अथवा नहीं । भले ही यह पाया जाए कि वह इस प्रकार निरर्हित था तब भी इससे कोई भी व्यवहारिक परिणाम नहीं निकलेगा क्योंकि उड़ीसा विधान सभा के विघटन के पश्चात् उसके निर्वाचन की अविधिमान्यता निरर्थक और निष्प्रभावी हो गई है.....

.....यह निष्कर्ष कि प्रत्यर्थी निरर्हित था, नामांकन की तारीख को विद्यमान तथ्यों पर आधारित था और जहां तक भविष्य की स्थिति का संबंध है, इसकी कोई सुसंगतता नहीं होगी और इसलिए उड़ीसा विधान सभा के विघटन को ध्यान में रखते हुए इसमें किसी भी पक्षकार का कोई व्यवहारिक हित नहीं है । न तो इससे अपीलार्थी को लाभ होगा और न किसी व्यवहारिक अर्थ में प्रत्यर्थी पर प्रभाव पड़ेगा तथा इस बारे में विचार करना पूर्ण रूप से सैद्धान्तिक मात्र होगा कि प्रत्यर्थी नामांकन की तारीख को निरर्हित था अथवा नहीं ।"

10. पुनः उच्चतम न्यायालय ने धरतीपकड़ मदन लाल बनाम राजीव गांधी (एआईआर 1987 एससी 1577) में निम्नलिखित मत व्यक्त किया :

" चुनौती के अधीन निर्वाचन 1981 के निर्वाचन से संबंधित है जिसकी कालावधि लोक सभा के विघटन पर 1984 में समाप्त हो गई, उसके पश्चात् दिसम्बर, 1984 में एक और अन्य साधारण निर्वाचन हुआ था और प्रत्यर्थी लोक सभा के लिए 25वें अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से पुनःनिर्वाचित हो गया था । 1984 के निर्वाचन की विधिमान्यता को दो पृथक निर्वाचन अर्जियों के माध्यम से प्रश्नगत किया गया था और दोनों ही अर्जियां खारिज कर दी गई थीं । प्रत्यर्थी के निर्वाचन की वैधता को अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी, एआईआर 1986 एससी 1253 और भगवती प्रसाद बनाम राजीव गांधी, (1986) 4 एससीसी 78 : (एआईआर 1986 एससी 1534) में बहाल रखा गया था । चूंकि आक्षेपित निर्वाचन लोक सभा से संबंधित है जो 1984 में विघटित कर दी गई थी, प्रत्यर्थी के निर्वाचन को वर्तमान कार्यवाहियों में अपास्त नहीं किया जा सकता भले ही निर्वाचन अर्जी विचारण पर अंत में मंजूर कर ली जाए क्योंकि प्रत्यर्थी 1981 में हुए आक्षेपित निर्वाचन के आधार पर लोक सभा का सदस्य नहीं बना हुआ है बल्कि 1984 में उसके पश्चातवर्ती निर्वाचन के आधार पर बना हुआ है । यदि हम अपील को मंजूर करते हैं और मामले को उच्च न्यायालय को प्रतिपरेषित करते हैं तब भी प्रत्यर्थी के निर्वाचन को निर्वाचन अर्जी के विचारण के पश्चात् अपास्त नहीं किया जा सकता क्योंकि निर्वाचन को अपास्त करने के लिए अनुतोष समय बीत जाने के कारण निरर्थक हो गया है । इस दृष्टि से प्रत्यर्थी के निर्वाचन को अपास्त करने के लिए अर्जी में उठाए गए आधार सैद्धान्तिक मात्र हो गए हैं । न्यायालय को किसी विवाद्यक का विचार करने के लिए तब तक विचार नहीं करना चाहिए जब तक कि पक्षकारों के बीच वह विवाद्यक जीवित न हो । यदि कोई विवाद्यक विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक मात्र हो तो उस दशा में उसका विनिश्चय किसी भी तरह से पक्षकारों की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा और यदि न्यायालय ऐसा विनिश्चय करता है तो उससे लोक समय की बर्बादी ही होगी । लार्ड विस्काउंट साइमन ने हाउस ऑफ लार्डस में सन लाइफ एस्योरेंस कंपनी ऑफ कनाडा बनाम जर्वीस, 1944 एससी 111 वाले मामले में अपने भाषण में यह मत व्यक्त किया : ' मैं यह नहीं मानता कि इस हाउस के पास अपीलों की सुनवाई करने के लिए जो प्राधिकार है उसका यह उचित प्रयोग होगा कि यदि वह इस मामले में किसी सैद्धान्तिक मात्र प्रश्न का विनिश्चय करने में अपना समय लगाता है जिसका उत्तर प्रत्यर्थी को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करता । इस हाउस द्वारा निपटारा किए जाने के लिए उपयुक्त अपील की एक अनिवार्य गुणवत्ता यह है कि पक्षकारों के बीच उस वास्तविक विवादित विषय पर विचार होना चाहिए जिसपर हाउस जीवित विवाद्यक के रूप में विनिश्चय करने के लिए विचार करता है ।' ये मत इस न्यायालय की अपीली अधिकारिता का प्रयोग करने में सुसंगत है ।"

11. आयोग ने निर्देश मामलों में उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत का लगातार अनुसरण किया है जहां वह सदस्य जिसके विरूद्ध परिवाद किया गया है, आयोग द्वारा राय दिए जाने से पूर्व और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रश्न का विनिश्चय किए जाने से पूर्व, संबंधित सदन का सदस्य नहीं रह गया है । ऐसे सभी मामलों में आयोग द्वारा अभिधारित सतत राय यह थी कि निर्देश निरर्थक हो गया था । ऐसे कुछ मामलों को उद्धृत करने के लिए श्री रणजी भाई चौधरी और गुजरात विधान सभा के बारह अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामले में (51 इएलआर 354) तारीख 17.06.1971 की आयोग की राय, श्री लजिन्दर सिंह बेदी और पंजाब विधान सभा के दो अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामले में (51 ईएलआर 360) तारीख 10.1.1972 की राय, श्री अवधेश सिंह और उत्तर प्रदेश विधान सभा के दस अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 2.7.1980 की राय, डा. जगन्नाथ मित्र, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 17.10.1990 की राय, श्री महादेव काशी राय पाटिल, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 27.10.1990 की राय, श्रीमती जयंती नटराजन, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 12.7.1992 की राय और सुश्री जयललीता, तमिलनाडु विधान सभा की सदस्य की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 29.8.1997 की आयोग की राय का इस संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है ।

12. डा. जगन्नाथ मिश्र का मामला (1989 का निर्देश मामला 2) तथ्यों और परिस्थितियों में वर्तमान मामले के समान था । उस मामले में उठाया गया प्रश्न राज्य सभा के तत्कालीन आसीन सदस्य डा. जगन्नाथ मिश्र की इस आधार पर अभिकथित निरर्हता के बारे में था कि वह एल. एन. मिश्र इन्स्टिट्यूट आफ इकोनोमिक डेवल्पमेंट एंड सोसियल चेन्ज, पटना के अध्यक्ष-सह-महानिदेशक का पद धारण कर रहे थे । उस मामले में तारीख 10-6-1989 की एक याचिका, तारीख 10-7-1989 को राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजी गई थी । उठाए गए प्रश्न पर आयोग द्वारा जांच के लंबित रहने के दौरान, डा. मिश्र ने राज्य सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया था और उनका त्यागपत्र 16-3-1990 को सदन के सभापति द्वारा स्वीकार किया गया था । आयोग ने तब यह राय दी थी कि डा. मिश्र के त्यागपत्र के अनुसरण में राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश निरर्थक हो गया है । आयोग ने उस मामले में दी गई अपनी राय में यह संप्रेक्षण किया कि :

> "तारीख 16-03-1990 को डा. मिश्र के त्यागपत्र के स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप वह उस दिन से राज्य सभा के सदस्य नहीं रह गए हैं । अतः यह प्रश्न कि क्या वह उस सभा के सदस्य के रूप बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं, इस समय विचार के लिए नहीं बचा है क्योंकि अब वह पहले से ही उस सभा के सदस्य नहीं हैं । इन परिस्थितियों में, आयोग की यह राय प्राप्त करने के लिए कि क्या डा. मिश्र राज्य सभा के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं, राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश निरर्थक हो गया है ।"

13. 1992 के निर्देश मामला सं. 1 में, जिसमें राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की गई तारीख 22-6-1992 की याचिका में उठाया गया प्रश्न यह था कि क्या श्रीमती जयन्ती नटराजन, तत्कालीन राज्य सभा की आसीन

सदस्या ने, इस आधार पर निरर्हता उपगत की है कि वह 5-5-1992 से 15-6-1992 तक केंद्रीय सरकार की अपर स्थायी कांउसेल थी । याचिका 30-6-1992 को आयोग को निर्दिष्ट की गई थी । श्रीमती नटराजन की सदस्यता की अवधि 29-6-1992 को समाप्त हो गई थी । आयोग ने निर्देश को निरर्थक माना क्योंकि सदन की उनकी सदस्यता 29-6-1992 को समाप्त हो गई थी और उस आशय की 12-7-1992 को राय दी थी ।

14. सुश्री जे. जयललिता से संबंधित निर्देश मामलों में (1993 का निर्देश मामला सं. 1(जी)-6 (जी) और 1994 का 1(जी) [अनुच्छेद 192 (2) के अधीन तमिलनाडु के राज्यपाल से तमिलनाडु विधान सभा से सुश्री जयललिता की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को उठाने वाले निर्देश] वह विधान सभा, जिसकी वह सदस्य थी और सदस्यता, जो मामलों में उठाए गए प्रश्न की विषयवस्तु थी, निर्देश मामलों के लंबित रहने के दौरान विघटित कर दी गई थी । विधान सभा के विघटन के पश्चात्, आयोग ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि मामले निरर्थक हो गए हैं । उस मामले में, लोकनाथ पधान बनाम बीरेन्द्र कुमार साहू (सुपर) में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेते हुए, आयोग ने यह संप्रेक्षण किया था :

> " उक्त प्रश्न के सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करने पर आयोग का यह मत है कि ऐसी कोई राय अब अनावश्यक होगी । इस प्रश्न पर कि क्या सुश्री जयललिता मई 1996 में पहले ही विघटित हो गई तमिलनाडु विधान सभा के पूर्वतर सदन के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरर्हित हो गई हैं । इस प्रक्रम पर कोई जांच, अब मात्र सैद्धान्तिक हित में ही होगी और निरर्थक प्रयास होगा । उपरोक्त प्रश्न पर की गई किसी उद्घोषणा से न तो उनकी वर्तमान प्रास्थिति पर किसी भी रूप में प्रभाव पड़ेगा, न ही ऐसी उद्घोषणा से इस प्रक्रम पर किसी अर्थपूर्ण प्रयोजन की पूर्ति होगी । यह एक सुव्यवस्थित न्यायिक परिपाटी है जो भारत में मानी और अनुपालन की जाती है कि यदि कोई विवाद्यक इस रूप में पूर्णतया सैद्धान्तिक है कि किसी भी रूप में उस पर विनिश्चय का पक्षकारों की स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो यह जनता के समय की बर्बादी होगी । वस्तुतः न्यायालयों के लिए ऐसे सैद्धान्तिक विवाद्यकों का विनिश्चय करने में अपने आपको लगाए रखना, प्राधिकार का उचित प्रयोग नहीं होगा । श्री बोबदे, लोकनाथ प्रधान बनाम बीरेन्द्र कुमार साहू (सुपर) के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेने में सही थे । उस मामले में, उड़ीसा विधान सभा के सफल अभ्यर्थी के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उसकी कतिपय कार्यों के निष्पादन के लिए उड़ीसा सरकार के साथ संविदा विद्यमान है और वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9क के अधीन निरर्हित हैं । उच्च न्यायालय ने निर्वाचन याचिका को खारिज कर दिया था, किंतु उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील लंबित थी, उसी समय उड़ीसा विधान सभा विघटित कर दी गई थी । उच्चतम न्यायालय ने राज्य विधान सभा के विघटन को ध्यान में रखते हुए अपील को निरर्थक हो जाने के कारण खारिज कर दिया था ।"

15. इस प्रकार, यह देखा जाएगा कि ऐसे सभी निर्देश मामलों में, जिनमें वह व्यक्ति, जिससे शिकायत संबंधित है, संबंधित सदन का सदस्य नहीं रह गया है, आयोग ने लगातार इस आशय की राय दी है कि मामला

निरर्थक हो गया है और उठाए गए प्रश्न पर आयोग द्वारा कोई राय केवल सैद्धान्तिक महत्व की ही होगी ।

16. उपर्युक्त सांविधानिक और विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और ऊपर वर्णित, पूर्व में सभी ऐसे निर्देश मामलों में आयोग द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से संगत, आयोग की सुविचारित राय यह है कि श्री नीलोत्पल बासु के राज्य सभा का सदस्य होने के लिए अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित वर्तमान निर्देश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निरर्थक हो गया है कि उनकी सदस्यता का कार्याकाल तारीख 2.4.2006 को समाप्त हो गया है और वे अब सदन के सदस्य नहीं हैं ।

17. तदनुसार, तारीख 20 मार्च, 2006 के निर्देश को, जहां तक वह श्री नीलोत्पल बासु की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित है, संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन आयोग की इस आशय की राय के साथ राष्ट्रपति को वापस भेजा जाता है कि वह निरर्थक हो गया है । याचिका में उठाए गए अन्य नौ संसद सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर पृथक रूप से विचार किया जा रहा है ।

ह./-	ह./-	ह./-
(नवीन बी. चावला)	(बी. बी. टंडन)	(एन. गोपालस्वामी)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 6 जून, 2006

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2006

S.O. 928(E).—The following Order made by the President is published for general information :-

ORDER

Whereas a petition dated the 8th March, 2006 of alleged disqualification of Shri Nilotpal Basu, the then sitting Member of Rajya Sabha and nine other Members of Parliament, namely, Shri Somnath Chatterjee, MP (Lok Sabha), Shri Md. Salim, MP (Lok Sabha), Shri Hannan Mollah, MP (Lok Sabha), Shri Laxman Seth, MP (Lok Sabha), Shri Amitava Nandy, MP (Lok Sabha), Shri Sudhanshu Sil, MP (Lok Sabha), Shri Tarit Baran Topdar, MP (Lok Sabha), Shri Bansagopal Chowdhury, MP (Lok Sabha) and Shri (Dr.) Sujan Chakraborty, MP (Lok Sabha) under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Mukul Roy, General Secretary, All India Trinamool Congress, 30B, Harish Chatterjee Street, Kolkata;

And whereas the said petitioner has averred in his petition that Shri Nilotpal Basu was holding an office of profit in West Bengal State Gramin Sanchay Society (GRASSO);

And whereas the opinion of the Election Commission had been sought by the President under a reference dated the 20th March, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Shri Nilotpal Basu and nine other Members of Parliament became subject to disqualification for being a Member of Parliament under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas the reference was received in the Election Commission on the 20th March, 2006 and during the pendency of the proceedings, the term of membership of Shri Nilotpal Basu had expired in the Rajya Sabha on the 2nd April, 2006;

And whereas the Election Commission has given its opinion (*vide* Annex) that in view of the fact that the term of the membership of Shri Nilotpal Basu has already expired in the Rajya Sabha on the 2nd April, 2006, and he is thus no longer a Member of Parliament, the said reference, in so far as it relates to the question of alleged disqualification of Shri Nilotpal Basu for being a member of Rajya Sabha, has become infructuous;

And whereas the Election Commission proposes to deal with the cases of alleged disqualification of nine other Members of Parliament separately as they stand on a different footing;

Now, therefore, I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby decide that the said petition of Shri Mukul Roy in so far as it relates to the alleged disqualification of Shri Nilotpal Basu for being member of the Rajya Sabha has become infructuous on account of the expiry of the term of membership of Shri Nilotpal Basu in the Rajya Sabha on the 2nd April, 2006.

20th June, 2006 President of India

[F. No. H-11026(13)/2006-Leg. II]

N. K. NAMPOOTHIRY, Jt. Secy. & Legislative Counsel

Anne.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

In re:
Alleged disqualification of Shri Nilotpal Basu, former member of the Rajya Sabha, under **Article 102 (1) (a) of the Constitution**

Reference Case No. 3 of 2006

[Reference from the President under Article 103 (2) of the Constitution]

OPINION

This is a reference dated 20th March, 2006 from the President of India, under Article 103 (2) of the Constitution, seeking opinion of the Election Commission on the question whether Shri Nilotpal Basu, who was then a setting member of the Rajya Sabha, Shri Somnath Chatterjee, MP (Lok Sabha), Shri Md. Salim, MP (Lok Sabha), Shri Hannan Mollah, MP (Lok Sabha), Shri Laxman Seth, MP (Lok Sabha), Shri Amitava Nandy, MP (Lok Sabha), Shri Sudhanshu Sil, MP (Lok Sabha), Shri Tarit Baran Topdar, MP (Lok Sabha), Shri Bansagopal Chowdhury, MP (Lok Sabha) and Shri (Dr.) Sujan Chakrabory, MP (Lok Sabha), have become subject to disqualification for being Member of the House concerned under Article 102 (1)(a) of the Constitution.

2. The question of alleged disqualification of the aforesaid ten MPs was raised in a single petition dated 8th March, 2006 submitted to the President by Sh. Mukul Roy, General Secretary, All India Trinamool Congress, 30B, Harish Chatterjee Street, Kolkata.

3. The present opinion relates to the question of alleged disqualification of Shri Nilotpal Basu, for being a member of the Rajya Sabha. The petitioner has alleged that Sh. Basu was holding an office in West Bengal State Gramin Sanchay Society (GRASSO). According to the petitioner, the said office was an office of profit, and hence, Sh. Basu had incurred disqualification for being a member of Rajya Sabha. The petitioner contended that in view thereof, Shri Basu should be disqualified from being a member of the Rajya Sabha, under Article 102 (1) (a) of the Constitution.

4. The reference from the President was received in the Commission on 20th March, 2006. The petition of Shri Mukul Roy was not accompanied by any document supporting his contention of alleged appointment of any of the Members of Parliament to the respective offices that were alleged to be offices of profit. Further, the petition of Shri Mukul Roy did not contain specific statement about the dates of appointments of the MPs including that of Shri Basu, to the offices referred to by the Petitioner. The Petitioner was, therefore, asked to furnish specific information in that regard vide the Commission's Notice dated 24th March, 2006. The Petitioner submitted a letter dated 15th April, 2006, enclosing therewith certain documents which again did not contain the specific information as called for. Therefore, the petitioner was again called upon, vide Notice on 3rd May, 2006, to furnish specific information, if any, by 24th May, 2006. The Petitioner submitted a letter in reply to the said Notice, on 24th May, 2006, contending, inter alia, that prima facie information was already provided by him.

5. Shri Basu was a sitting member of Rajya Sabha when the reference was received from the President and also when notice was issued to the petitioner to furnish specific information regarding alleged appointment of the ten MPs mentioned in the petition. In the meantime, the term of Shri Nilotpal Basu as Member of Rajya Sabha expired on 2nd April, 2006, and he has ceased to be a member of that House with effect from that date.

6. In view of the fact that the term of Shri Nilotpal Basu as member of the Rajya Sabha has since expired, his case stands on a different footing vis-à-vis the other nine MPs referred to in the petition dated 8th March, 2006, and hence the case of Shri Basu has been delinked from that of the others, and this Opinion is being tendered on the question of alleged disqualification of Shri Basu.

7. In view of the retirement of Sh. Basu from membership of the Rajya Sabha on 2.4.2006, the preliminary issue whether the question of his alleged disqualification raised in the petition referred, survives for any opinion of the Commission under Article 103(2) of the Constitution, needs to be decided at the outset.

8. The proceedings before the Commission in cases of references from the President and Governors under Articles 103 (2) and 192(2) are quasi-judicial proceedings. Hence,

in such matters, the Commission is guided by and follows the principles, procedures and policy adopted by the Supreme Court and High Courts. As a general principle, the Courts look into live issues between the parties and do not undertake to decide an issue which is purely academic or has become infructuous on account of any supervening event. In cases where during the pendency of an election appeal, the candidate whose election was under challenge ceased to be a member of the House concerned, on his death or on account of his resignation from the seat in the House concerned or where the House itself got dissolved, the Supreme Court has treated the appeal as infructuous and dismissed the appeal as such. In *Podipireddy Achuta Desai Vs. Chinnam Joga Rao* [(1987) Supp SCC 42], where the House was dissolved during the pendency of the election appeal, the Supreme Court held:

> "The questions raised in this election appeal are of some importance. We also see the force of the submissions urged on behalf of the appellant. All the same, having regard to the fact that fresh elections have already taken place and the appeal has become redundant in that sense, we will be underaking a futile exercise if we examine the validity or otherwise of the view taken by the High Court in dismissing the election petition. Under the circumstances without expressing any view, one way or the other, on the validity or otherwise of the decision of the High Court, we direct that this appeal shall stand disposed of with no order as to costs."

9. Earlier ,the Supreme Court in the case of ,*Loknath Padhan vs. Birendra Kumar Sahu*(AIR 1974 SC 505),had held:

> "Assembly being dissolved, the setting aside of the election of the respondent would have no meaning or consequence and hence the Court should refuse to embark on a discussion of the merits of the question arising in the appeal. We think there is great force in this preliminary contention urged on behalf the respondent. It is a well settled practice recongnised and followed in India as well as England that a Court should not undertake to decide an issue, unless it is a living issue between the parties. If an issue is purely academic in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties it would be waste of public time and indeed not proper exercise of authority for the Court to engage itself in deciding it.....
>
> .....In the present case, the Orissa Legislative Assembly being dissolved, it has become academic to consider whether on the date when the nomination was filed, the respondent was disqualified under S. 9-A. Even If it is found that he was so disqualified, it would have no practical consequence, because the invalidation of his election after the dissolution of the Orissa Legislative Assembly would be meaningless and ineffectual.....

.....The finding that the respondent was disqualified would be based on the facts existing at the date of nomination and it would have no relevance so far as the position at a future point of time may be concerned, and therefore, in view of the dissolution of the Orissa Legislative Assembly, it would have no practical interest for either of the parties. Neither would it benefit the appellant nor would it affect the respondent in any pratical sense and it would be wholly academic to consider whether the respondent was disqualified on the date of nomination."

10. Again, the Supreme Court observed in Dhartipakar Madan Lal Vs Rajiv Gandhi (AIR 1987 SC 1577) as follows :

"The election under challenge relates to 1981, its term expired in 1984 on the dissolution of the Lok Sabha, thereafter-another general election was held in December 1984 and the respondent was again elected from 25th Amethi Constituency to the Lok Sabha. The validity of the election field in 1984 was questioned by means of two separate election petitions and both the petitions have been dismissed. The validity of respondent's election has been upheld in Azhar Hussain V. Rajiv Gandhi, AIR 1986 SC 1253 and Bhagwati Prasad v. Rajiv Gandhi (1986) 4 SCC 78: (AIR 1986 SC 1534). Since the impugned election relates to the Lok Sabha which was dissolved in 1984 the respondent's election cannot be set aside in the present proceedings even if the election petition is ultimately allowed on trial as the respondent is a continuing member of the Lok Sabha not on the basis of the impugned election held in 1981 but on the basis of his subsequent election in 1984. Even if we allow the appeal and remit the case to the High Court the respondent's election cannot be set aside after trial of the election petition as the relief for setting aside the election has been rendered in fructuous by lapse of time. In this view grounds raised in the petition for setting aside the election of the respondent have been rendered academic. Court should not undertake to decide an issue unless it is a living issue between the parties. If an issue is purely academic in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties, if would be waste of public time to engage itself in deciding it. Lord Viscount Simon in his speech in the House of Lords in Sun Life Assurance Company of Canada v. Jervis, 1944 AC 111 observed; "I do not think that it would be a proper exercise of the Authority which this House possesses to hear appeals if it occupies time in this case in deciding an academic question, the answer to which cannot affect the respondent in any way. It is an essential quality of an appeal fit to be disposed of by this House that there should exist between the parties to a matter in actual controversy which the House undertakes to decide as a living issue." These observations are relevant in exercising the appellate jurisdiction of this Court."

11. The Commission has consistently followed the above judicial principle in the reference cases where the member, against whom complaint was made, ceased to be a member of the House concerned, before opinion was tendered by the Commission and the question decided by the President or the Governor. In all such cases, the consistent view held by the Commission was that the reference had become infructuous. To cite a few such cases, the Commission's Opinion dated 17-06-1971 in the reference case

regarding alleged disqualification of Sh. Ranjibhai Choudhary and twelve other members of Gujarat Legislative Assembly (51 ELR 354), Opinion dated 10-1-1972 in the matter of alleged disqualification of Sh. Lajinder Singh Bedi and two other members of Punjab Legislative Assembly (51 ELR 360), Opinion dated 2-7-1980 in the case of alleged disqualification of Sh. Avdhesh Singh and ten other members of Uttar Pradesh Legislative Assembly, Opinion dated 17-10-1990, in the case of alleged disqualification of Dr. Jaganath Mishra, member of Rajya Sabha, Opinion dated 27-10-1990 in the case of alleged disqualification of Sh. Mahadeo Kashiray Patil, member of Rajya Sabha, Opinion dated 12-7-1992 in the case of alleged disqualification of Smt. Jayanthi Natarajan, member of Rajya Sabha, and Opinion dated 29-8-1997, regarding alleged disqualification of Ms. J.Jayalalitha, member of Tamil Nadu Legislative Assembly, may be seen in this context.

12. In the case of Dr. Jaganath Mishra (Reference Case of 2 of 1989), the question raised in that case was about alleged disqualification of Dr. Jagannath Mishra, then sitting Member of Rajya Sabha, on the ground that he was holding the office of Chairman-cum-Director General of the L.N.Mishra Institute of Economic Development and Social Change, Patna. In that case, a petition dated 10.6.1989, was referred to the Commission by the President, on 10.7.1989. During the pendency of inquiry by the Commission into the question raised, Dr. Mishra resigned his seat in the Rajya Sabha, and his resignation was accepted by the Chairman of the House on 16.3.1990. The Commission then tendered the opinion that following the resignation of Dr. Mishra, the reference from the President had become infructous. The Commission in its Opinion tendered in that case, observed :

> " Consequent upon the acceptance of resignation of Dr. Mishra on 16-03-1990, he is no longer a member of the Council of States from that day. Therefore, the question whether he is disqualified for continuing as a member of that Council no longer survives for consideration at present as he is already not a member of that Council now. In these circumstances, the reference received from the President seeking the opinion of the Commission whether Dr. Mishra has become subject to disqualification to continue as member of the Council of States has become infructuous."

13. In Reference Case No. 1 of 1992 the question raised in the petition dated 22.6.1992 submitted before the President, was whether Smt. Jayanthi Natarajan, then sitting Member of Rajya Sabha, had incurred disqualification on the ground that she was

an Additional Central Govt. Standing Counsel from 5-5-1992 to 15-6-1992. The petition was referred to the Commission on 30.6.1992. The term of membership of Smt. Natarajan expired on 29-6-1992. The Commission considered the reference as infructuous as her membership of the House had come to an end on 29-6-1992, and tendered opinion to that effect on 12.7.1992.

14. In the Reference Cases relating to Ms. J. Jayalalitha, (Reference Case Nos. 1(G) - 6 (G) of 93 and 1 (G) of 94, [references from the Governor of Tamil Nadu under Article 192 (2)] raising the question of alleged disqualification of Ms. Jayalalitha from membership of Tamil Nadu Legislative Assembly, the Assembly in which she was a member and the membership of which was the subject matter of the question raised in the cases, was dissolved during the pendency of the reference cases. Following the dissolution of the Assembly, the Commission took the view that the cases had become infructous. In that case, relying on the decision of the Supreme Court in *Loknath Padhan Vs. Birendera Kumar Sahu* (Supra), the Commission observed :

> "Having considered all relevant aspects of the said question, the Commission is of the view that any such opinion now would be unnecessary. Any enquiry, at this stage, into the question whether Ms. Jayalalitha had become subject to disqualification for continuing as a member of the earlier House of the Tamil Nadu Legislative Assembly, already dissolved in May, 1996, would be of mere academic interest now, and would be an exercise in futility. Any pronouncement on the above question would not affect her present status, one way or the other, nor would such pronouncement serve any meaningful purpose at this stage. It is a well settled judicial practice, recognised and followed in India, that if an issue is purely academic, in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties, it would be waste of public time, and indeed not proper exercise of authority for the courts to engage themselves in deciding such academic issues. Shri Bobde was right in placing reliance on the decision of the Supreme Court in the case of Loknath Padhan vs. Birendra Kumar Sahu (Supra). In that case, the election of successful candidate to the Orissa Legislative Assembly was challenged on the ground that he had a subsisting contract with the Government of Orissa for the execution of certain works and that he was disqualified under Section 9A of the Representation of the People Act, 1951. The High Court dismissed the election petition, but an appeal was pending before the Supreme Court, when, in the meanwhile, the Orissa Legislative Assembly was dissolved. The Supreme Court dismissed the appeal, as having become infructuous, in view of dissolution of the State Legislative Assembly."

15. It would, thus, be seen that in all reference cases in which the person to whom the complaint pertained ceased to be a member of the House concerned during the pendency of the proceedings, the Commission has consistently tendered opinion to the effect that the case had been rendered infructuous, and any opinion by the Commission on the question raised would only be of academic value.

16. Having regard to the above constitutional and legal position, and consistent with the view taken by the Commission in all such reference cases in the past, mentioned above, the Commission is of the considered opinion that the present reference on the question of alleged disqualification of Shri Nilotpal Basu for being a member of the Rajya Sabha has become infructuous, in view of the fact that the term of his membership in the Rajya Sabha has expired on 2.4.2006, and he is no longer a member of the House.

17. Accordingly, the reference dated 20th March, 2006, in so far as it relates to the question of alleged disqualification of Shri Nilotpal Basu, is hereby returned to the President with the Commission's opinion, under Article 103(2) of the Constitution, to the effect that the same has become infructuous. The question of alleged disqualification of other nine Members of Parliament raised in the petition, is being considered separately.

(Navin B.Chawla)
Election Commissioner

(B.B.Tandon)
Chief Election Commissioner

(N.Gopalaswami)
Election Commissioner

Place : New Delhi
Dated: 6th June, 2006

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2006

का.आ. 929(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :–

आदेश

श्रीमती जमुना देवी, विपक्ष की नेता, मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन श्री शिवराज सिंह चौहान जो लोक सभा के तत्कालीन आसीन सदस्य थे और श्री कृष्ण मुरारी मोघे, जो लोकसभा के आसीन सदस्य हैं, की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 26 मार्च, 2006 की याचिका प्रस्तुत की गई हैं;

और उक्त याची ने अपनी याचिका में यह अभिकथन किया है कि श्री शिवराज सिंह चौहान ने, माध्यम के, जो फर्म और सोसाइटी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक निकाय है पदेन अध्यक्ष का पद धारण किया था और इस प्रकार वे लाभ का पद धारण कर रहे थे;

और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन एक निर्देश, तारीख 29 मार्च, 2006 द्वारा इस प्रश्न के संबंध में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई थी कि क्या श्री शिवराज सिंह चौहान, जो संसद (लोक सभा) के तत्कालीन आसीन सदस्य थे और श्री कृष्ण मुरारी मोघे, जो संसद (लोक सभा) के आसीन सदस्य हैं, संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन संसद सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं;

और निर्वाचन आयोग में निर्देश 29 मार्च, 2006 को प्राप्त हुआ था और कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, श्री चौहान ने 10 मई, 2006 को लोक सभा में अपने स्थान से त्याग-पत्र दे दिया था । इस तथ्य को, लोक सभा सचिवालय द्वारा तारीख 10 मई, 2006 की अपनी अधिसूचना सं० 21/3/2006/टी द्वारा यह सूचित करते हुए अधिसूचित किया गया था कि लोक सभा अध्यक्ष द्वारा उनका त्याग पत्र 10 मई, 2006 से स्वीकार कर लिया गया है;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि इस तथ्य के कारण कि श्री चौहान ने 10 मई, 2006 को लोक सभा में अपने स्थान से त्याग-पत्र दे दिया था और इस प्रकार वे अब संसद सदस्य नहीं हैं, उक्त निर्देश, जहां तक वह श्री शिवराज सिंह चौहान के लोक सभा का सदस्य बने रहने के लिए उनकी अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित है, निरर्थक हो गया है;

और निर्वाचन आयोग श्री कृष्ण मुरारी मोघे की अभिकथित निरर्हता के मामले पर पृथक रुप से कार्यवाही करने का प्रस्ताव करता है;

अतः, अब, मैं, आ० प० जै० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूं कि श्रीमती जमुना देवी की उक्त याचिका, जहां तक वह श्री शिवराज सिंह चौहान के संसद (लोक सभा) का सदस्य बने रहने के लिए उनकी अभिकथित निरर्हता से संबंधित है, 10 मई, 2006 को श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लोक सभा की अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिए जाने के कारण निरर्थक हो गई है ।

20 जून, 2006

भारत का राष्ट्रपति

[फा. सं. एच-11026(14)/2006-लेग. II]

एन. के. नम्पूथिरी, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी

1873GI/06—3

उपाबन्ध

भारत निर्वाचन आयोग

निर्देश :
संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन पूर्व लोक सभा सदस्य श्री शिवराज सिंह चौहान की अभिकथित निरर्हता

2006 का निर्देश मामला सं. 14
[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

राय

यह संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त तारीख 29 मार्च, 2006 का निर्देश है, जिसके द्वारा इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री शिवराज सिंह चौहान जो लोक सभा के तत्कालीन आसीन सदस्य थे और श्री कृष्ण मुरारी मौघे, जो लोक सभा के आसीन सदस्य हैं, संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन लोक सभा के सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं अथवा नहीं ।

2. श्री चौहान और श्री मोघे की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न श्रीमती जमुना देवी, विपक्ष की नेता, मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई तारीख 26.03.2006 की याचिका में उठाया गया था । यह राय श्री चौहान की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित है । श्री मोघे की निरर्हता के संबंध में उठाए गए प्रश्न पर पृथक रूप से विचार किया जा रहा है ।

3. याचिका में, जहां तक वह श्री चौहान से संबंधित है, याची ने यह अभिकथन किया है कि श्री चौहान ने, माध्यम के, जो फर्म और सोसाइटी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक निकाय है और जो विज्ञापन, फिल्म निर्माण, प्रकाशन आदि से जुड़ा एक बहुउद्देशीय निकाय है, पदेन अध्यक्ष का पद धारण किया था । याची के अनुसार श्री चौहान माध्यम का अध्यक्ष होने के कारण धनीय और गैर धनीय, सभी प्रकार के फायदे ले रहे थे और सभी प्रकार के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रणों का प्रयोग कर रहे थे । चूंकि याचिका में यह अवधारण करने के लिए कि क्या उठाया गया प्रश्न अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति की अधिकारिता के अंतर्गत आएगा अथवा नहीं, अपेक्षित आधारिक जानकारी के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट कथन अंतर्विष्ट नहीं था, इसलिए आयोग ने अपनी तारीख 5 अप्रैल, 2006 की सूचना द्वारा याची को 28.04.06 तक अभिकथित नियुक्ति की तारीख के संबंध में विनिर्दिष्ट जानकारी, जो कि इस दलील को कि वह पद अनुच्छेद 102(1)(क) के अर्थान्तर्गत एक लाभ का पद था, सिद्ध करने वाले सुसंगत दस्तावेजों द्वारा समर्थित हो, प्रस्तुत करने के लिए कहा था ।

4. याची ने तारीख 25.04.2006 का एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उसने यह कथन किया कि श्री चौहान अन्य अनेक निकायों, निगम, परिषद, बोर्ड आदि के अध्यक्ष का पद धारण कर रहे थे । तथापि, याची ने श्री चौहान की इनमें से किसी भी पद पर या मध्य प्रदेश माध्यम के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की तारीख का उल्लेख नहीं किया था । उसने मध्य प्रदेश माध्यम के संविधान की, 25.11.2000 तक अद्यतन प्रति और कतिपय अन्य दस्तावेज जैसे कि मध्य प्रदेश माध्यम के कर्मचारिवृंद/पदधारियों की सूची, उनके वेतन आदि संलग्न किए । चूंकि याची द्वारा प्रस्तुत उत्तर में अपेक्षित आधारिक ब्यौरे अंतर्विष्ट नहीं थे, अतः, याची को पुनः तारीख 11 मई, 2006 की आयोग की सूचना द्वारा 31.05.2006 तक ब्यौरे प्रस्तुत करने का एक और अवसर दिया गया था ।

5. जब इस विषय से संबंधित कार्यवाहियां इस प्रक्रम पर थीं, श्री चौहान ने 10 मई, 2006 को लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया । इस संबंध में आयोग को लोक सभा सचिवालय की तारीख 10 मई, 2006 की अधिसूचना संख्या 21/3/2006/टी की एक प्रति 12 मई, 2006 को प्राप्त हुई थीं । उक्त अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया था कि श्री चौहान ने लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया था और लोक सभा अध्यक्ष ने उनका त्यागपत्र 10 मई, 2006 से स्वीकार कर लिया था ।

6. श्री चौहान द्वारा लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दिए जाने को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा विचार किए जाने हेतु उदभूत प्रारंभिक विवाद्यक यह है कि क्या आयोग को निर्दिष्ट याचिका में उठाया गया उनकी अभिकथित निरर्हता का प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन आयोग की किसी राय के लिए अब भी जीवित है अथवा नहीं ।

7. संविधान के अनुच्छेद 103(2) और अनुच्छेद 192(2) के अधीन राष्ट्रपति और राज्यपालों से निर्देशों के मामलों में आयोग के समक्ष कार्यवाहियां न्यायिककल्प कार्यवाहियां होती हैं । अतः, ऐसे मामलों में आयोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अंगीकार किए गए सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और नीति द्वारा मार्गदर्शित होता है और उनका अनुसरण करता है । एक साधारण सिद्धांत के रूप में न्यायालय पक्षकारों के बीच जीवित विवाद्यकों पर विचार करते हैं और ऐसे विवाद्यक पर विनिश्चय करने के लिए विचार नहीं करते जो विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक मात्र होता है या किसी बाद में घटित होने वाली घटना के कारण निरर्थक हो गया है । ऐसे मामलों में जिनमें निर्वाचन अपील के लंबित रहने के दौरान, अभ्यर्थी जिसके निर्वाचन को चुनौती दी गई थी, उसकी मृत्यु या संबंधित सदन में स्थान से उसके त्यागपत्र पर या जहां स्वयं सदन ही विघटित कर दिया गया हो, संबंधित सदन का सदस्य नहीं रहता, उच्चतम न्यायालय ने अपील को निरर्थक अपील के रूप में माना है और उस आधार पर अपील को खारिज कर दिया है । पोडीपीरेड्डी अच्यूत देसाई बनाम चिन्नम जोगाराव [(1987) सप्लिमेंटरी एससीसी 42] के मामले में जहां सदन निर्वाचन अपील के लंबित रहने के दौरान विघटित कर दिया गया था, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :

> " इस निर्वाचन अपील में उठाए गए प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण हैं । हम अपीलार्थी की ओर से दी गई दलीलों में बल भी देख रहे हैं । इसी तरह, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नए रूप से

निर्वाचन पहले ही हो चुके हैं और इस रूप में अपील निरर्थक हो गई है, यदि हम निर्वाचन अर्जी को खारिज करने में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए मत की विधिमान्यता या अन्य प्रारूप में जांच करें तो हम बेकार में ही अपनी शक्ति गवाएंगे । हम, इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय की विनिश्चय की विधिमान्यता पर या अन्य पहलू पर कोई राय चाहे वह किसी तरह की हो, व्यक्त किए बिना यह निदेश देते हैं कि यह अपील खर्चे के बारे में कोई आदेश किए बिना निपटाई गई समझी जाएगी ।"

8. पूर्व में उच्चतम न्यायालय ने लोकनाथ पधान बनाम वीरेन्द्र कुमार साहु (एआईआर 1974 एससी 505) के मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था :

" विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण, प्रत्यर्थी के निर्वाचन को अपास्त करना निरर्थक होगा और उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, अतः न्यायालय को अपील में उद्भूत प्रश्न के गुणागुण पर विचार-विमर्श करने से इंकार कर देना चाहिए । हम यह मानते हैं कि प्रत्यर्थी की ओर से दी गई इस प्राथमिक दलील में काफी बल है । भारत तथा इंग्लैंड में मान्यताप्राप्त और अनुसरित सुस्थापित यह पद्धति है कि न्यायालय को ऐसे विवाद्यक का विनिश्चय करने के लिए तब तक विचार नहीं करना चाहिए जब तक कि वह विवाद्यक पक्षकारों के बीच में जीवित न हो । यदि कोई विवाद्यक विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक मात्र हो और उसके विनिश्चय से पक्षकारों की स्थिति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो यह लोक समय की बर्बादी ही होगी और न्यायालय के लिए इसका विनिश्चय करने में स्वयं को लगाए रखने में उसके प्राधिकार का उचित प्रयोग भी नहीं है.....

.....प्रस्तुत मामले में, उड़ीसा विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण इस बारे में विचार करना सैद्धान्तिक मात्र हो गया है कि क्या उस तारीख को जब नामांकन फाइल किया गया था, प्रत्यर्थी नियम 9-क के अधीन निरर्हित था अथवा नहीं । भले ही यह पाया जाए कि वह इस प्रकार निरर्हित था तब भी इससे कोई भी व्यवहारिक परिणाम नहीं निकलेगा क्योंकि उड़ीसा विधान सभा के विघटन के पश्चात् उसके निर्वाचन की अविधिमान्यता निरर्थक और निष्प्रभावी हो गई है.....

.....यह निष्कर्ष कि प्रत्यर्थी निरर्हित था, नामांकन की तारीख को विद्यमान तथ्यों पर आधारित था और जहां तक भविष्य की स्थिति का संबंध है, इसकी कोई सुसंगतता नहीं होगी और इसलिए उड़ीसा विधान सभा के विघटन को ध्यान में रखते हुए इसमें किसी भी पक्षकार का कोई व्यवहारिक हित नहीं है । न तो इससे अपीलार्थी को लाभ होगा और न किसी व्यवहारिक अर्थ में प्रत्यर्थी पर प्रभाव पड़ेगा तथा इस बारे में विचार करना पूर्ण रूप से सैद्धान्तिक मात्र होगा कि प्रत्यर्थी नामांकन की तारीख को निरर्हित था अथवा नहीं ।"

9. पुनः उच्चतम न्यायालय ने धरतीपकड़ मदन लाल बनाम राजीव गांधी (एआईआर 1987 एससी 1577) में निम्नलिखित मत व्यक्त किया :

" चुनौती के अधीन निर्वाचन 1981 के निर्वाचन से संबंधित है जिसकी कालावधि लोक सभा के विघटन पर 1984 में समाप्त हो गई, उसके पश्चात् दिसम्बर, 1984 में एक और अन्य साधारण निर्वाचन हुआ था और

प्रत्यर्थी लोक सभा के लिए 25वें अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से पुनःनिर्वाचित हो गया था । 1984 के निर्वाचन की विधिमान्यता को दो पृथक निर्वाचन अर्जियों के माध्यम से प्रश्नगत किया गया था और दोनों ही अर्जियां खारिज कर दी गई थीं । प्रत्यर्थी के निर्वाचन की वैधता को अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी, एआईआर 1986 एससी 1253 और भगवती प्रसाद बनाम राजीव गांधी, (1986) 4 एससीसी 78 : (एआईआर 1986 एससी 1534) में बहाल रखा गया था । चूंकि आक्षेपित निर्वाचन लोक सभा से संबंधित है जो 1984 में विघटित कर दी गई थी, प्रत्यर्थी के निर्वाचन को वर्तमान कार्यवाहियों में अपास्त नहीं किया जा सकता भले ही निर्वाचन अर्जी विचारण पर अंत में मंजूर कर ली जाए क्योंकि प्रत्यर्थी 1981 में हुए आक्षेपित निर्वाचन के आधार पर लोक सभा का सदस्य नहीं बना हुआ है बल्कि 1984 में उसके पश्चातवर्ती निर्वाचन के आधार पर बना हुआ है । यदि हम अपील को मंजूर करते हैं और मामले को उच्च न्यायालय को प्रतिपरेषित करते हैं तब भी प्रत्यर्थी के निर्वाचन को निर्वाचन अर्जी के विचारण के पश्चात् अपास्त नहीं किया जा सकता क्योंकि निर्वाचन को अपास्त करने के लिए अनुतोष समय बीत जाने के कारण निरर्थक हो गया है । इस दृष्टि से प्रत्यर्थी के निर्वाचन को अपास्त करने के लिए अर्जी में उठाए गए आधार सैद्धान्तिक मात्र हो गए हैं । न्यायालय को किसी विवाद्यक का विचार करने के लिए तब तक विचार नहीं करना चाहिए जब तक कि पक्षकारों के बीच वह विवाद्यक जीवित न हो । यदि कोई विवाद्यक विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक मात्र हो तो उस दशा में उसका विनिश्चय किसी भी तरह से पक्षकारों की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा और यदि न्यायालय ऐसा विनिश्चय करता है तो उससे लोक समय की बर्बादी ही होगी । लार्ड विस्काउंट साइमन ने हाउस ऑफ लार्डस में सन लाइफ एस्योरेंस कंपनी ऑफ कनाडा बनाम जर्वीस, 1944 एससी 111 वाले मामले में अपने भाषण में यह मत व्यक्त किया : ' मैं यह नहीं मानता कि इस हाउस के पास अपीलों की सुनवाई करने के लिए जो प्राधिकार है उसका यह उचित प्रयोग होगा कि यदि वह इसं मामले में किसी सैद्धान्तिक मात्र प्रश्न का विनिश्चय करने में अपना समय लगाता है जिसका उत्तर प्रत्यर्थी को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करता । इस हाउस द्वारा निपटारा किए जाने के लिए उपयुक्त अपील की एक अनिवार्य गुणवत्ता यह है कि पक्षकारों के बीच उस वास्तविक विवादित विषय पर विचार होना चाहिए जिसपर हाउस जीवित विवाद्यक के रूप में विनिश्चय करने के लिए विचार करता है ।' ये मत इस न्यायालय की अपीली अधिकारिता का प्रयोग करने में सुसंगत है ।'

10. आयोग ने निर्देश मामलों में उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत का लगातार अनुसरण किया है जहां वह सदस्य जिसके विरूद्ध परिवाद किया गया है, आयोग द्वारा राय दिए जाने से पूर्व और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रश्न का विनिश्चय किए जाने से पूर्व, संबंधित सदन का सदस्य नहीं रह गया है । ऐसे सभी मामलों में आयोग द्वारा अभिधारित सतत राय यह थी कि निर्देश निरर्थक हो गया था । ऐसे कुछ मामलों को उद्धृत करने के लिए श्री रणजी भाई चौधरी और गुजरात विधान सभा के बारह अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामले में (51 इएलआर 354) तारीख 17.06.1971 की आयोग की राय, श्री लजिन्दर सिंह बेदी और पंजाब विधान सभा के दो अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामले में (51 ईएलआर 360) तारीख 10.1.1972 की राय, श्री अवधेश सिंह और उत्तर प्रदेश विधान सभा के दस अन्य सदस्यों की अभिकथित

निरर्हता के मामले में तारीख 2.7.1980 की राय, डा. जगन्नाथ मिश्र, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 17.10.1990 की राय, श्री महादेव काशी राय पाटिल, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 27.10.1990 की राय, श्रीमती जयंती नटराजन, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 12.7.1992 की राय और सुश्री जयललीता, तमिलनाडु विधान सभा की सदस्य की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 29.8.1997 की आयोग की राय का इस संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है ।

11. डा. जगन्नाथ मिश्र का मामला (1989 का निर्देश मामला 2) तथ्यों और परिस्थितियों में वर्तमान मामले के समान था । उस मामले में उठाया गया प्रश्न राज्य सभा के तत्कालीन आसीन सदस्य डा. जगन्नाथ मिश्र की इस आधार पर अभिकथित निरर्हता के बारे में था कि वह एल. एन. मिश्र इन्स्टिट्यूट आफ इकोनोमिक डेवल्पमेंट एंड सोसियल चेन्ज, पटना के अध्यक्ष-सह-महानिदेशक का पद धारण कर रहे थे । उस मामले में तारीख 10-6-1989 की एक याचिका, तारीख 10-7-1989 को राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजी गई थी । उठाए गए प्रश्न पर आयोग द्वारा जांच के लंबित रहने के दौरान, डा. मिश्र ने राज्य सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया था और उनका त्यागपत्र 16-3-1990 को सदन के सभापति द्वारा स्वीकार किया गया था । आयोग ने तब यह राय दी थी कि डा. मिश्र के त्यागपत्र के अनुसरण में राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश निरर्थक हो गया है । आयोग ने उस मामले में दी गई अपनी राय में यह संप्रेक्षण किया कि :

> "तारीख 16-03-1990 को डा. मिश्र के त्यागपत्र के स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप वह उस दिन से राज्य सभा के सदस्य नहीं रह गए हैं । अतः यह प्रश्न कि क्या वह उस सभा के सदस्य के रूप बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं, इस समय विचार के लिए नहीं बचा है क्योंकि अब वह पहले से ही उस सभा के सदस्य नहीं हैं । इन परिस्थितियों में, आयोग की यह राय प्राप्त करने के लिए कि क्या डा. मिश्र राज्य सभा के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं, राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश निरर्थक हो गया है ।"

12. 1992 के निर्देश मामला सं. 1 में, जिसमें राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की गई तारीख 22-6-1992 की याचिका में उठाया गया प्रश्न यह था कि क्या श्रीमती जयन्ती नटराजन, तत्कालीन राज्य सभा की आसीन सदस्या ने, इस आधार पर निरर्हता उपगत की है कि वह 5-5-1992 से 15-6-1992 तक केंद्रीय सरकार की अपर स्थायी कांउसेल थी । याचिका 30-6-1992 को आयोग को निर्दिष्ट की गई थी । श्रीमती नटराजन की सदस्यता की अवधि 29-6-1992 को समाप्त हो गई थी । आयोग ने निर्देश को निरर्थक माना क्योंकि सदन की उनकी सदस्यता 29-6-1992 को समाप्त हो गई थी और उस आशय की 12-7-1992 को राय दी थी ।

13. सुश्री जे. जयललिता से संबंधित निर्देश मामलों में (1993 का निर्देश मामला सं. 1(जी)-6 (जी) और 1994 का 1(जी) [अनुच्छेद 192 (2) के अधीन तमिलनाडु के राज्यपाल से तमिलनाडु विधान सभा से सुश्री जयललिता की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को उठाने वाले निर्देश] वह विधान सभा, जिसकी वह सदस्य थी

और सदस्यता, जो मामलों में उठाए गए प्रश्न की विषयवस्तु थी; निर्देश मामलों के लंबित रहने के दौरान विघटित कर दी गई थी । विधान सभा के विघटन के पश्चात्, आयोग ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि मामले निरर्थक हो गए हैं । उस मामले में, लोकनाथ पधान बनाम बीरेन्द्र कुमार साहू (सुपर) में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेते हुए, आयोग ने यह संप्रेक्षण किया था :

> " उक्त प्रश्न के सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करने पर आयोग का यह मत है कि ऐसी कोई राय अब अनावश्यक होगी । इस प्रश्न पर कि क्या सुश्री जयललिता मई 1996 में पहले ही विघटित हो गई तमिलनाडु विधान सभा के पूर्वतर सदन के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरर्हित हो गई हैं । इस प्रक्रम पर कोई जांच. अब मात्र सैद्धान्तिक हित में ही होगी और निरर्थक प्रयास होगा । उपरोक्त प्रश्न पर की गई किसी उद्घोषणा से न तो उनकी वर्तमान प्रास्थिति पर किसी भी रूप में प्रभाव पड़ेगा, न ही ऐसी उद्घोषणा से इस प्रक्रम पर किसी अर्थपूर्ण प्रयोजन की पूर्ति होगी । यह एक सुव्यवस्थित न्यायिक परिपाटी है जो भारत में मानी और अनुपालन की जाती है कि यदि कोई विवाद्यक इस रूप में पूर्णतया सैद्धान्तिक है कि किसी भी रूप में उस पर विनिश्चय का पक्षकारों की स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो यह जनता के समय की बर्बादी होगी । वस्तुतः न्यायालयों के लिए ऐसे सैद्धान्तिक विवाद्यकों का विनिश्चय करने में अपने आपको लगाए रखना, प्राधिकार का उचित प्रयोग नहीं होगा । श्री बोबदे, लोकनाथ प्रधान बनाम बीरेन्द्र कुमार साहू (सुपर) के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेने में सही थे । उस मामले में, उड़ीसा विधान सभा के सफल अभ्यर्थी के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उसकी कतिपय कार्यों के निष्पादन के लिए उड़ीसा सरकार के साथ संविदा विद्यमान है और वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9क के अधीन निरर्हित हैं । उच्च न्यायालय ने निर्वाचन याचिका को खारिज कर दिया था, किंतु उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील लंबित थी, उसी समय उड़ीसा विधान सभा विघटित कर दी गई थी । उच्चतम न्यायालय ने राज्य विधान सभा के विघटन को ध्यान में रखते हुए अपील को निरर्थक हो जाने के कारण खारिज कर दिया था ।"

14. इस प्रकार, यह देखा जाएगा कि ऐसे सभी निर्देश मामलों में, जिनमें वह व्यक्ति, जिससे शिकायत संबंधित है, संबंधित सदन का सदस्य नहीं रह गया है, आयोग ने लगातार इस आशय की राय दी है कि मामला निरर्थक हो गया है और उठाए गए प्रश्न पर आयोग द्वारा कोई राय केवल सैद्धान्तिक महत्व की ही होगी । आयोग ने अभी-अभी लोक सभा की सदस्यता से श्रीमती सोनिया गांधी की अभिकथित निरर्हता से संबंधित 2006 के निर्देश मामले सं0 6,7,11 और 71 में तथा राज्य सभा की सदस्यता से श्री अनिल अंबानी की निरर्हता से संबंधित 2006 के निर्देश मामला सं0 38 में यही दृष्टिकोण अपनाया है ।

15. उपर्युक्त सांविधानिक और विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और ऊपर वर्णित, पूर्व में सभी ऐसे निर्देश मामलों में आयोग द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से संगत, आयोग की सुविचारित राय यह है कि श्री

शिवराज सिंह चौहान के लोक सभा का सदस्य होने के लिए अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित वर्तमान निर्देश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निरर्थक हो गया है कि श्री चौहान ने 10 मई, 2006 को लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया है और वे अब सदन के सदस्य नहीं हैं ।

16. तदनुसार, उक्त निर्देश को, जहां तक वह श्री शिवराज सिंह चौहान की निरर्हता के प्रश्न से संबंधित है, संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन आयोग की इस आशय की राय के साथ राष्ट्रपति को वापस भेजा जाता है कि वह निरर्थक हो गया है । उसी निर्देश में निर्दिष्ट श्री कृष्ण मुरारी मोघे की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर पृथक रूप से विचार किया जा रहा है और उस विषय में राय सम्यक् अनुक्रम में प्रस्तुत की जाएगी ।

ह./-	ह./-	ह./-
(नवीन बी. चावला)	(बी. बी. टंडन)	(एन. गोपालस्वामी)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 6 जून, 2006

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2006

S.O.929(E).—The following Order made by the President is published for general information :-

ORDER

Whereas a petition dated the 26th March, 2006 of alleged disqualification of Shri Shivraj Singh Chauhan, the then sitting Member of Parliament (Lok Sabha) and Shri Krishan Murari Moghe, a sitting Member of Parliament (Lok Sabha) under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Smt. Jamuna Devi, Leader of Opposition, Madhya Pradesh Vidhan Sabha;

And whereas the said petitioner has averred in her petition that Shri Shivraj Singh Chauhan occupied the post of ex-officio Chairman of Madhyam, a body registered under the Firms and Societies Act, and thus he was holding an office of profit;

And whereas the opinion of the Election Commission had been sought by the President under a reference dated the 29th March, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Shri Shivraj Singh Chauhan, the then sitting Member of Parliament (Lok Sabha) and Shri Krishan Murari Moghe, a sitting Member of Parliament (Lok Sabha) became subject to disqualification for being a Member of Parliament under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas the reference was received in the Election Commission on the 29th March, 2006 and during the pendency of the proceedings, Shri Chauhan resigned his seat in the Lok Sabha on 10th May, 2006 which fact was notified by the Lok Sabha Secretariat vide its notification No. 21/3/2006/T dated the 10th May, 2006 informing the acceptance of his resignation by the Speaker with effect from the 10th May, 2006;

And whereas the Election Commission has given its opinion (*vide* Annex) that in view of the fact that Shri Chauhan has resigned his seat in the Lok Sabha on 10th May, 2006 and he is thus no longer a Member of the Lok Sabha, the said reference, in so far as it relates to the question of alleged disqualification of Shri Shivraj Singh Chauhan for being a Member of Lok Sabha, has become infructuous;

And whereas the Election Commission proposes to deal with the case of alleged disqualification of Shri Krishan Murari Moghe separately;

Now, therefore, I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby decide that the said petition of Smt. Jamuna Devi in so far as it relates to the alleged disqualification of Shri Shivraj Singh Chauhan for being a Member of Parliament (Lok Sabha) has become infructuous on account of the resignation of Shri Shivraj Singh Chauhan of his membership in the Lok Sabha on the 10th May, 2006.

20th June, 2006 President of India

[F. No. H-11026(14)/2006-Leg. II]

N. K. NAMPOOTHIRY, Jt. Secy. & Legislative Counsel

Annex

ELECTION COMMISSION OF INDIA

In re:

Alleged disqualification of Sh. Shivraj Singh Chauhan, former member of the Lok Sabha under Article 102 (1) (a) of the Constitution

Rererence Case No. 14 of 2006

[Reference from the President under Article 103 (2) of the Constitution]

OPINION

This is a reference dated 29th March, 2006 received from the President of India, under Article 103 (2) of the Constitution, seeking opinion of the Election Commission on the question whether Sh. Shivraj Singh Chauhan, a then sitting member of the Lok

Sabha, and Sh. Krishan Murari Moghe, a sitting Member of Lok Sabha, have become subject to disqualification for being a Member of Lok Sabha under Article 102 (1)(a) of the Constitution.

2. The question of alleged disqualification of Sh. Chauhan and Sh. Moghe, was raised in a petition dated 26-03-2006 submitted to the President by Smt. Jamuna Devi, Leader of Opposition , Madhya Pradesh Vidhan Sabha. The present Opinion relates to the question of alleged disqualification of Sh. Chauhan. The question raised with regard to disqualification of Sh. Moghe is being considered separately.

3. In the petition, in so far as it related to Sh. Chauhan, the petitioner alleged that Sh. Chauhan occupied the post of ex-officio Chairman of Madhyam, a body registered under the Firms and Societies Act, a multi purpose body involved in advertising, film production, publication etc. According to the petitioner, Sh. Chauhan was enjoying all benefits, pecuniary and non-pecuniary, and exercising all administrative and financial control by virtue of being the Chairman of Madhyam. As the petition did not contain any specific statement regarding the date of appointment of Sh. Chauhan to the office of Chairman of Madhyam, the basic information required to determine whether the question raised would fall under the jurisdiction of the President under Article 103 (1), the Commission, vide its notice dated 5th April, 2006, asked petitioner to furnish specific information by 28-04-06, about the date of alleged appointment, supported by relevant documents to substantiate the contention that the office was an office of profit within the meaning of Article 102 (1) (a).

4. The petitioner submitted a letter dated 25-04-2006 in which she stated that Sh. Chauhan was holding the office of Chairman of several other Bodies, Corporation, Parishad, Board, etc. However, the petitioner did not mention the date of appointment of Sh. Chauhan to any of these offices or to the offices of Chairman, Madhya Pradesh Madhyam. She enclosed a copy of the Constitution of Madhya Pradesh Madhyam, updated as on 25-11-2000, and certain other documents such as list of staff/officials of Madhya Pradesh, their pay, etc. As the reply submitted by the petitioner did not contain the requisite basic details, she was given another opportunity to submit the details by 31-05-2006, vide the Commission's notice dated 11th May, 2006.

5. When the proceedings of the matter were at this stage, Sh. Chauhan resigned his seat in the Lok Sabha on 10th May, 2006. A copy of the Notification No. 21/3/2006/T, dated 10th May, 2006 of the Lok Sabha Secretariat, in this regard, was received in the Commission on 12th May, 2006. In the said notification, it was mentioned that Sh. Chauhan had resigned his seat in the Lok Sabha and his resignation was accepted by the Speaker w.e.f.10th May, 2006.

6. In view of the resignation by Sh. Chauhan of his seat in the Lok Sabha, the preliminary issue arising for consideration of the Commission is whether the question of his alleged disqualification raised in the petition referred to the Commission, survives for any opinion of the Commission under Article 103(2) of the Constitution.

7. The proceedings before the Commission in cases of references from the President and Governors under Articles 103 (2) and 192(2) are quasi-judicial proceedings. Hence, in such matters, the Commission is guided by and follows the principles, procedures and policy adopted by the Supreme Court and High Courts. As a general principle, the Courts look into live issues between the parties and do not undertake to decide an issue which is purely academic or has become infructuous on account of any supervening event. In cases where during the pendency of an election appeal, the candidate whose election was under challenge ceased to be a member of the House concerned, on his death or on account of his resignation from the seat in the House concerned or where the House itself got dissolved, the Supreme Court has treated the appeal as infructuous and dismissed the appeal as such. In *Podipireddy Achuta Desai Vs. Chinnam Joga Rao* [(1987) Supp SCC 42], where the House was dissolved during the pendency of the election appeal, the Supreme Court held:

> "The questions raised in this election appeal are of some importance. We also see the force of the submissions urged on behalf of the appellant. All the same, having regard to the fact that fresh elections have already taken place and the appeal has become redundant in that sense, we will be underaking a futile exercise if we examine the validity or otherwise of the view taken by the High Court in dismissing the election petition. Under the circumstances without expressing any view, one way or the other, on the validity or otherwise of the decision of the High Court, we direct that this appeal shall stand disposed of with no order as to costs."

8. Earlier ,the Supreme Court in the case of *Loknath Padhan vs. Birendra Kumar Sahu*(AIR 1974 SC 505),had held:

"Assembly being dissolved, the setting aside of the election of the respondent would have no meaning or consequence and hence the Court should refuse to embark on a discussion of the merits of the question arising in the appeal. We think there is great force in this preliminary contention urged on behalf the respondent. It is a well settled practice recongnised and followed in India as well as England that a Court should not undertake to decide an issue, unless it is a living issue between the parties. If an issue is purely academic in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties it would be waste of public time and indeed not proper exercise of authority for the Court to engage itself in deciding it.....

.....In the present case, the Orissa Legislative Assembly being dissolved, it has become academic to consider whether on the date when the nomination was filed, the respondent was disqualified under S. 9-A. Even if it is found that he was so disqualified, it would have no practical consequence, because the invalidation of his election after the dissolution of the Orissa Legislative Assembly would be meaningless and ineffectual.....

.....The finding that the respondent was disqualified would be based on the facts existing at the date of nomination and it would have no relevance so far as the position at a future point of time may be concerned, and therefore, in view of the dissolution of the Orissa Legislative Assembly, it would have no practical interest for either of the parties. Neither would it benefit the appellant nor would it affect the respondent in any pratical sense and it would be wholly academic to consider whether the respondent was disqualified on the date of nomination."

9. Again, the Supreme Court observed in Dhartipakar Madan Lal Vs Rajiv Gandhi (AIR 1987 SC 1577) as follows :

The election under challenge relates to 1981, its term expired in 1984 on the dissolution of the Lok Sabha, thereafter-another general election was held in December 1984 and the respondent was again elected from 25th Amethi Constituency to the Lok Sabha. The validity of the election field in 1984 was questioned by means of two separate election petitions and both the petitions have been dismissed. The validity of respondent's election has been upheld in Azhar Hussain V. Rajiv Gandhi, AIR 1986 SC 1253 and Bhagwati Prasad v. Rajiv Gandhi (1986) 4 SCC 78: (AIR 1986 SC 1534). Since the impugned election relates to the Lok Sabha which was dissolved in 1984 the respondent's election cannot be set aside in the present proceedings even if the election petition is ultimately allowed on trial as the respondent is a continuing member of the Lok Sabha not on the basis of the impugned election held in 1981 but on the basis of his subsequent election in 1984. Even if we allow the appeal and remit the case to the High Court the respondent's election cannot be set aside after trial of the election petition as the relief for setting aside the election has been rendered in fructuous by lapse of time. In this view grounds raised in the petition for setting aside the election of the respondent have been rendered academic. Court should not undertake to decide an issue unless it is a living issue between the parties. If an issue is purely academic in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties, if would be waste of public time to engage itself in deciding it. Lord Viscount Simon in his speech in the House of

Lords in Sun Life Assurance Company of Canada v. Jervis, 1944 AC 111 observed; "I do not think that it would be a proper exercise of the Authority which this House possesses to hear appeals if it occupies time in this case in deciding an academic question, the answer to which cannot affect the respondent in any way. It is an essential quality of an appeal fit to be disposed of by this House that there should exist between the parties to a matter in actual controversy which the House undertakes to decide as a living issue." These observations are relevant in exercising the appellate jurisdiction of this Court."

10. The Commission has consistently followed the above judicial principle in the reference cases where the member, against whom complaint was made, ceased to be a member of the House concerned, before opinion was tendered by the Commission and the question decided by the President or the Governor. In all such cases, the consistent view held by the Commission was that the reference had become infructuous. To cite a few such cases, the Commission's Opinion dated 17-06-1971 in the reference case regarding alleged disqualification of Sh. Ranjibhai Choudhary and twelve other members of Gujarat Legislative Assembly (51 ELR 354), Opinion dated 10-1-1972 in the matter of alleged disqualification of Sh. Lajinder Singh Bedi and two other members of Punjab Legislative Assembly (51 ELR 360), Opinion dated 2-7-1980 in the case of alleged disqualification of Sh. Avdhesh Singh and ten other members of Uttar Pradesh Legislative Assembly, Opinion dated 17-10-1990, in the case of alleged disqualification of Dr. Jaganath Mishra, member of Rajya Sabha, Opinion dated 27-10-1990 in the case of alleged disqualification of Sh. Mahadeo Kashiray Patil, member of Rajya Sabha, Opinion dated 12-7-1992 in the case of alleged disqualification of Smt. Jayanthi Natarajan, member of Rajya Sabha, and Opinion dated 29-8-1997, regarding alleged disqualification of Ms. J.Jayalalitha, member of Tamil Nadu Legislative Assembly, may be seen in this context.

11. The case of Dr. Jaganath Mishra (Reference Case of 2 of 1989) was identical in facts and circumstances, to the present case. The question raised in that case was about alleged disqualification of Dr. Jagannath Mishra, then sitting Member of Rajya Sabha, on the ground that he was holding the office of Chairman-cum-Director General of the L.N.Mishra Institute of Economic Development and Social Change, Patna. In that case, a petition dated 10.6.1989, was referred to the Commission by the President, on 10.7.1989. During the pendency of inquiry by the Commission into the question raised, Dr. Mishra resigned his seat in the Rajya Sabha, and his resignation was accepted by the Chairman of the House on 16.3.1990. The Commission then tendered the opinion that

following the resignation of Dr. Mishra, the reference from the President had become infructous. The Commission in its Opinion tendered in that case, observed :

> " Consequent upon the acceptance of resignation of Dr. Mishra on 16-03-1990, he is no longer a member of the Council of States from that day. Therefore, the question whether he is disqualified for continuing as a member of that Council no longer survives for consideration at present as he is already not a member of that Council now. In these circumstances, the reference received from the President seeking the opinion of the Commission whether Dr. Mishra has become subject to disqualification to continue as member of the Council of States has become infructous."

12. In Reference Case No. 1 of 1992 in which the question raised in the petition dated 22.6.1992 submitted before the President, was whether Smt.Jayanthi Natarajan, then sitting Member of Rajya Sabha, had incurred disqualification on the ground that she was an Additional Central Govt. Standing Counsel from 5-5-1992 to 15-6-1992. The petition was referred to the Commission on 30.6.1992. The term of membership of Smt. Natarajan expired on 29-6-1992. The Commission considered the reference as infructous as her membership of the House had come to an end on 29-6-1992, and tendered opinion to that effect on 12.7.1992.

13. In the Reference Cases relating to Ms. J.Jayalalitha, (Reference Case Nos. 1(G) - 6 (G) of 93 and 1 (G) of 94, [references from the Governor of Tamil Nadu under Article 192 (2)] raising the question of alleged disqualification of Ms. Jayalalitha from membership of Tamil Nadu Legislative Assembly, the Assembly in which she was a member and the membership of which was the subject matter of the question raised in the cases, was dissolved during the pendency of the reference cases. Following the dissolution of the Assembly, the Commission took the view that the cases had become infructous. In that case, relying on the decision of the Supreme Court in *Loknath Padhan Vs. Birendera Kumar Sahu* (Supra), the Commission observed :

> "Having considered all relevant aspects of the said question, the Commission is of the view that any such opinion now would be unnecessary. Any enquiry, at this stage, into the question whether Ms. Jayalalitha had become subject to disqualification for continuing as a member of the earlier House of the Tamil Nadu Legislative Assembly,

already dissolved in May, 1996, would be of mere academic interest now, and would be an exercise in futility. Any pronouncement on the above question would not affect her present status, one way or the other, nor would such pronouncement serve any meaningful purpose at this stage. It is a well settled judicial practice, recognised and followed in India, that if an issue is purely academic, in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties, it would be waste of public time, and indeed not proper exercise of authority for the courts to engage themselves in deciding such academic issues. Shri Bobde was right in placing reliance on the decision of the Supreme Court in the case of Loknath Padhan vs. Birendra Kumar Sahu (Supra). In that case, the election of successful candidate to the Orissa Legislative Assembly was challenged on the ground that he had a subsisting contract with the Government of Orissa for the execution of certain works and that he was disqualified under Section 9A of the Representation of the People Act, 1951. The High Court dismissed the election petition, but an appeal was pending before the Supreme Court, when, in the meanwhile, the Orissa Legislative Assembly was dissolved. The Supreme Court dismissed the appeal, as having become infructuous, in view of dissolution of the State Legislative Assembly."

14. It would, thus, be seen that in all reference cases in which the person to whom the complaint pertained ceased to be a member of the House concerned, the Commission has consistently tendered opinion to the effect that the case had been rendered infructuous, and any opinion by the Commission on the question raised would only be of academic value. The Commission has taken the same view in the recent reference cases Nos. 6,7,11,36 and 71 of 2006 regarding alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi from membership of Lok Sabha, and in reference case No. 38 of 2006, regarding alleged disqualification of Sh. Anil Ambani from membership of Rajya Sabha.

15. Having regard to the above constitutional and legal position, and consistent with the view taken by the Commission in all such reference cases in the past, mentioned above, the Commission is of the considered opinion that the present reference on the question of alleged disqualification of Sh. Shivraj Singh Chauhan for being a member of the Lok Sabha has become infructuous, in view of the fact that Sh. Chauhan has resigned his seat in the Lok Sabha on 10th May, 2006, and is thus no longer a member of the House.

16. Accordingly, the said reference, in so far as it relates to the question of disqualification of Sh. Shivraj Singh Chauhan, is hereby returned to the President with the Commission's opinion, under Article 103(2) of the Constitution, to the effect that the same has become infructuous. The question of alleged disqualification of Sh. Krishan Murari Moghe, referred in the same reference, is being considered separately, and Opinion in that matter will be tendered in due course.

(Navin B.Chawla)
Election Commissioner

(B.B.Tandon)
Chief Election Commissioner

(N.Gopalaswami)
Election Commissioner

Place : New Delhi
Dated: 6th June, 2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.